RB/Estt.No.120 /2005

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. E(D&A) 2005/RG 6-23 New Delhi dated 18.7.2005

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units etc.
(As per Standard Lists)

Sub: Exercise of disciplinary powers in respect of railway servant transferred from one Railway/Division to another Railway/Division or Unit etc. - Clarification regarding.

A case has come to the notice of this Ministry where disciplinary proceedings against a Railway officer working in Railway Claims Tribunal was instituted by the General Manager of the parent Railway because the alleged misconduct was committed by the officer while working on the zonal Railway. The exercise of disciplinary powers as above was not correct because at the time of taking disciplinary action the concerned officer was working under the control of the Chairman, Railway Claims Tribunal who has also been vested with the disciplinary powers in respect of staff/officers working in the Railway Claims Tribunal, in terms of Notification bearing No. GSR 845/E dated 19.9.1989. Since the disciplinary proceedings had been instituted by an authority who was not competent to do so, the proceedings against the concerned officer had to be dropped subsequently.

2. In this connection, attention is invited to instructions contained in Board's letter No.E(D&A) 60/RG 6-30 dated 28.7.1962 read with their letters No.E(D&A) 65/RG 6-6 dated 1.3.1967 and No.E(D&A) 72/RG 6-13 dated 16.10.1973 wherein it had, inter-alia, been laid down that it would be procedurally wrong for an authority to initiate and finalise the disciplinary proceedings against an employee who is not under its administrative control. These instructions also deal with the situations where a Railway servant commits an offence while working in one Railway administration but the same comes to light only after his transfer to another Railway administration or another division and it becomes necessary to take disciplinary action against him for the offence. Disciplinary action in such cases should be taken by the Railway/Division on which the person concerned might be working at the time of taking disciplinary action in consultation with the Railway/Division where the offence was committed. The consultation with the parent Railway however, would be limited to obtaining the relevant information/documents which may be required for processing the disciplinary action. In a rare case where it is considered necessary that action should be taken by the Railway/Division where the offence was committed, the Railway servant concerned should be transferred to that Railway/Division which should thereafter only initiate and finalize the disciplinary action. In other words, disciplinary action by an authority in the parent Railway should be taken only after the Railway servant concerned has been brought under the administrative control of the authority proposing to take action.

3. Further, Rule 15 of RS(D&A) Rules, 1968 specifically provides about the course of action to be taken in respect of Railway employees who are on deputation to Central/State/Local Government or other authority. Similarly, Rule 16 makes provision about officers on deputation from other Central/State Governments, etc. to the Railways. Roles of Lending Authority and the Borrowing Authority have been clearly specified in these rules. Provisions contained in these Rules should be kept in view while initiating disciplinary proceedings against the Railway employees on deputation to other departments, etc. or employees belonging to other departments taken on deputation to the Railways.

...2/-

4. The above instructions may please be brought to the notice of all concerned authorities for their guidance and compliance and it may be impressed upon them that they should carefully ascertain their jurisdiction before instituting disciplinary proceedings in a case so that the unfortunate type of situation as has occurred in the case referred to in Para 1 above, could be avoided.

Please acknowledge receipt.

(R. Vijayan Nair)
Dy. Director Establishment(D&A)
Railway Board

No. E(D&A) 2005/RG 6-23 New Delhi dated 18.7.2005

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi (with 35 spares)
3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C. Ferozshah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies)
5. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies).
6. The Secretary, RBSS 'Group B' Officers' Association.
7. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
8. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association.
9. The Secretary General, AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, RBSS 'Group A' Officers' Association, Room No.506, Rail Bhavan, New Delhi.
11. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No.2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

PS/MR, PS/MSR(V), PS/MSR(N)

Sr.PPSs to CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, Secretary.

AM(Commn.), Adv(S), Adv(IR), Adv(Vig), Adv(Conf.), EDV(E), EDE, EDE(Res.), EDE(RRB), EDE(N), EDPG, JS, JS(E&P), JS(G), DV(M), DV(A) DE(N), DE(G), DE(D&A), DS(D&A), DS(EO)I, JDE(GP), JDE(L), JDE(LL), JDV(S), JDV(A&P), DS(G), US(E), US(A), US(Confd.), DD(RCT), DDE(D&A), DDE(LR)I, US(D&A), E(O)I, E(O)II, E(O) III, E(O)III(Spl.), ERB-I, ERB-II, ERB-D, ERB-V, E(GP), Vig.-I, E(NG)I, E(SCT) I & II, E(Rep) I, II & III, Security(E) and E(LR)I branches of Railway Board.

*****

आर बी/ईस्ट सं. 120/2005

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए)2005/आर जी 6-23 नई दिल्ली, दिनांक 18 .7.2005

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक डाक सूची के अनुसार).

विषय : एक रेलवे/मंडल से दूसरे रेलवे/ मंडल या इकाई आदि में स्थानांतरित रेल सेवक के संबंध में अनुशासनिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस मंत्रालय के ध्यान में एक मामला आया है जहां रेल दावा अधिकरण में कार्यरत एक रेलवे अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही मूल रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा शुरू की गई थी क्योंकि उस अधिकारी ने कथित कदाचार उस क्षेत्रीय रेलवे में कार्यरत रहने के दौरान किया था. उपर्युक्त के अनुसार, जिस तरह अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग किया गया था, वह सही नहीं था क्योंकि अनुशासनिक कार्रवाई करते समय संबंधित अधिकारी अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण के नियंत्रणाधीन कार्यरत था जिन्हें 19.9.1989 के सा का नि सं. 845/ ई के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, रेल दावा अधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं. चूंकि, अनुशासनिक कार्यवाही एक ऐसे प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था इसलिए बाद में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध उस कार्यवाही को बंद करना पड़ा.

2. इस संबंध में, बोर्ड के 1.3.1967 के पत्र सं. ई (डी एंड ए)65/आर जी 6-6 तथा 16.10.1973 के पत्र सं. ई (डी एंड ए)72/आर जी 6-13 के पत्रों के साथ पठित 28.7.1962 के पत्र सं. ई (डी एंड ए)60/आर जी 6-30 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि किसी प्राधिकारी के लिए कार्यविधि की दृष्टि से यह गलत होगा कि वह किसी ऐसे कर्मचारी, जो उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करे तथा उसे अंतिम रूप दे. ये अनुदेश ऐसी परिस्थितियों से भी संबंधित है जहां कोई रेल कर्मचारी किसी एक रेल प्रशासन में कार्य करते समय कोई अपराध करता है परंतु यह मामला उसके किसी दूसरे रेल प्रशासन या किसी दूसरे मंडल में स्थानांतरण होने के बाद ही प्रकाश में आता है और उस अपराध के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है. ऐसे मामलों में अनुशासनिक

...2/-

कार्रवाई उस रेलवे/मंडल, जहां अपराध किया गया था, के परामर्श से उस रेलवे/मंडल द्वारा की जानी चाहिए जहां अनुशासनिक कार्रवाई करते समय संबंधित व्यक्ति कार्यरत हो. बहरहाल, मूल रेलवे से परामर्श संबद्ध सूचना/दस्तावेज प्राप्त करने तक ही सीमित होगा जो अनुशासनिक कार्रवाई की कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित है. किसी विरले मामले में, जहां यह आवश्यक समझा जाता है कि कार्रवाई उस रेलवे/मंडल द्वारा की जानी चाहिए जहां अपराध किया गया था, वहां संबंधित रेल सेवक को उस रेल/मंडल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए और इसके बाद ही अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए तथा उसे अंतिम रूप देना चाहिए. दूसरे शब्दों में, मूल रेलवे में किसी प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई तभी शुरू करनी चाहिए जब संबंधित रेल सेवक को अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव करने वाले प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाया जा चुका हो.

3. इसके अलावा, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 15 में उन रेल सेवकों, जो केन्द्रीय/ राज्य/स्थानीय सरकार या अन्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विशेष रूप से व्यवस्था है. इसी प्रकार, नियम 16 में रेलों में अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारों, आदि से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के बारे में व्यवस्था है. ऋण प्राधिकारी तथा आदाता प्राधिकारी की भूमिका को भी इन नियमों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है. अन्य विभागों आदि में प्रतिनियुक्ति पर गए रेल कर्मचारियों या रेलों में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करते समय इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखा जाए.

4. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों को सर्व-संबंधित प्राधिकारियों के दिशानिर्देशन तथा अनुपालन के लिए उनकी सूचना में लाया जाए और इस बात पर बल दिया जाए कि वे किसी मामले में अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने से पहले अपने क्षेत्राधिकार का सावधानीपूर्वक पता लगा लें ताकि खेदजनक स्थिति, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित मामले में हुआ है, से बचा जा सके.

कृपया पावती दें.

(आर. विजयन नायर)
उप निदेशक स्था (अनुशासन एवं अपील)
रेलवे बोर्ड.

... 3/-